



इस्तीफे की मांग को लेकर सीएम के आवास का घेराव करने की कोशिश.. @ नम्मा बेंगलूर

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | बुधवार, 18 जून, 2025 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | website : <https://www.shubhlabhdaily.com> | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | मूल्य-6 रु. | वर्ष-7 | अंक-167

ईरान के दूसरे सेना प्रमुख भी मारे गए  
खामनेई अकेले पड़े



तेहरान, 17 जून (एजेंसियां)।

इजराइल और ईरान की बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इजराइल लगातार ईरानी सेना के शीर्ष नेताओं को निशाना बना रहा है। मंगलवार को इजराइल ने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार भी कर लिया है।

इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इस संघर्ष में ईरान ने न सिर्फ अपने देश के शीर्ष सैन्य कमांडरों को खोया है बल्कि कई परमाणु संयंत्रों और अहम सैन्य ठिकाने भी ध्वस्त हो गए हैं। इसी बीच मंगलवार को इजराइली सेना ने ईरान के एक और शीर्ष कमांडर अली शादमानी को भी मार गिराया है। इजराइल के लगातार हमलों के चलते ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई अकेले पड़ गए हैं। शादमानी ईरान की सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने चार दिन पहले ही यह पद संभाला था। उन्हें इजराइली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद पिछले शुक्रवार को इजराइली हमले में मारे गए थे। **10पर**

भयावह शक्ति लेने लगा इजराइल और ईरान का संघर्ष

## ईरान के ध्वस्त होने का खतरा तेहरान छोड़कर जा रहे लोग

नई दिल्ली, 17 जून (एजेंसियां)।

ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के और बढ़ने की आशंका पर भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने लोगों से तुरंत तेहरान छोड़ने को कहा है। उनसे भारतीय दूतावास के सम्पर्क में रहने और तेहरान से बाहर आने के लिए उचित व्यवस्था न हो पाने तक सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (भारतीय मूल के व्यक्ति) जो अपने संसाधनों का उपयोग करके तेहरान से बाहर जा सकते हैं, उन्हें शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है।

भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ईरान की राजधानी तेहरान से भारतीय छात्रों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है और अन्य भारतीयों को भी शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। इजराइल लगातार ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर निशाना बना रहा है। इसके जवाब में ईरान भी इजराइल पर



मिसाइल हमले कर रहा है। विदेश मंत्रालय और ईरान का भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर अपडेट जारी कर रहे हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए भारतीयों को शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। जो अपने वाहन से जाने में सक्षम हैं, वे तेहरान से निकलें। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया की सीमा के माध्यम से ईरान छोड़ने में मदद की गई है। दूतावास सभी संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समुदाय के साथ लगातार सम्पर्क

भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए जारी की नई एडवाइजरी

ईरान में फंसे 10 हजार छात्रों को सुरक्षित निकालने पर ध्यान

भारतीय छात्रों को सड़क मार्ग से निकालने की अनुमति मिली

तेल संकट के आसार, भारत ने 50 लाख टन का रखा रिजर्व

और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिससे सहायता प्राप्त की जा सकती है।

पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी है, बल्कि वहां रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर छात्रों के लिए गंभीर सुरक्षा संकट पैदा कर दिया है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे लगभग 10,000 भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी की पहल एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और मानवीय कदम है। भारत सरकार ने ईरान सरकार से राजनयिक स्तर पर अपने छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए मार्ग देने का अनुरोध किया था जिसे तेहरान ने स्वीकार करके सड़क मार्ग से उन्हें निकालने की अनुमति दी है।

**10पर**

खामनेई के खात्मे के बाद ही क्षेत्र में शांति आएगी : नेतन्याहू



तेहरान, 17 जून (एजेंसियां)।

इजराइल ने सोमवार की रात को लड़ाकू विमानों ने तेहरान में लाइव प्रसारण के दौरान सरकारी टेलीविजन हेडक्वार्टर पर बमबारी कर दी। हालांकि ईरान ने भी इजराइल पर लगभग 400 बैलेस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है। एबीसी न्यूज से इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई के खात्मे के साथ ही क्षेत्र में शांति आएगी। इस बीच, मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजराइल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इजराइल ने अधिकतम ईरानी मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दिए। ईरान में कम से कम 224 लोग मारे गए हैं और 1,200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के जवाबी हमलों में इजराइल में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और करीब 500 लोग घायल हुए हैं।

एक वरिष्ठ इजराइली सैन्य अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि इजराइल ने रातों-रात ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़े दर्जनों स्थलों पर हमला किया और ईरान के सैन्य नेतृत्व को भागने पर मजबूर कर दिया। उक्त अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने अभी तक ईरान की भूमिगत फोड़ों परमाणु सुविधा को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन इसकी संभावना बनी हुई है। **10पर**

इजराइल-ईरान युद्ध तेज हुआ तो भारत पर भी पड़ेगा असर

भारत ने एहतियात में उठाए कई अहम कदम



तेल की कीमतों से लेकर व्यापार तक होगा प्रभावित

नई दिल्ली, 17 जून (एजेंसियां)।

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष पांचवें दिन पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य अफसरों तक को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। पश्चिम एशिया की ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इजराइल और ईरान का संघर्ष अब पूरी तरह युद्ध में बदलता हुआ दिख रहा है, ऐसे में इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। दोनों देशों में भारतीयों की अच्छी-खासी संख्या भी पूर्ण युद्ध की स्थिति में खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत फिलहाल ईरान से कच्चा तेल आयात

बार होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाला मार्ग एक ऐसा कारक है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वैश्विक पेट्रोलियम पदार्थों की खपत का 21 प्रतिशत इसी मार्ग से गुजरता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इस मार्ग से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए शीर्ष गंतव्य हैं। ओमान भी भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करता है।

यूरोप के साथ भारत का करीब 80 फीसदी वस्तु व्यापार लाल सागर के जॉर्जिया होता है। अमेरिका के साथ भी काफी व्यापार इसी मार्ग से होता है। लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के जॉर्जिया भारत कुल 34 फीसदी निर्यात करता है। **10पर**

तेल संकट की वैश्विक आशंका के बीच भारत को मिला अवसर

अंडमान सागर में मिला तेल का विशाल खजाना

नई दिल्ली, 17 जून (एजेंसियां)।

अंडमान सागर में तेल के विशाल भंडार का पता चला है। यह खोज ऐसे नाजुक और महत्वपूर्ण समय में हुई जब मध्य-पूर्व के तनावपूर्ण माहौल में तेल का संकट संभावित दिख रहा है। इसे भारत के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान सागर में गायना जैसे विशाल तेल भंडार की खोज होने अब पूर्ण होने पर है। इस खोज में लगभग 2 लाख करोड़ लीटर (लगभग 22 बिलियन बैरल) कच्चे तेल के भंडार की संभावना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को 3.7 ट्रिलियन डॉलर से 20 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। यह खोज न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है, बल्कि देश को वैश्विक तेल बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने एक बयान में कहा है कि 2016 के बाद से सरकार ने तेल और गैस की खोज को गति दी है। इसके तहत ओपन एक्जरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के तहत 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के सेडिमेंट्री बेसिन में से करीब



भारत की अर्थव्यवस्था में 5 गुना वृद्धि की संभावना

दो लाख करोड़ लीटर कच्चा तेल मिलने की उम्मीद

1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अन्वेषण के लिए खोल दिया गया है। ओएएलपी के 9वें दौर में 38 प्रतिशत बिड्स इन नए क्षेत्रों के लिए थे, और अगले दौर में यह हिस्सा 80 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, 1948 के पुराने नियमों को बदलकर नए आयात

फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल ने नियामक स्पष्टता प्रदान की है। तेल खोज के क्षेत्र में भारत सरकार बहुत ही गंभीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने वित्तीय वर्ष 2024 में ओएनजीसी ने

541 कुएं खोदे, जिनमें 103 अन्वेषण और 438 डेवलपमेंट कुएं शामिल हैं। यह 37 वर्षों में सबसे अधिक है। कंपनी ने इस दौरान 37,000 करोड़ का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय भी किया। पुरी ने कहा, गायना में 41वें कुएं पर तेल मिला था, प्रत्येक की लागत 100 मिलियन डॉलर थी। भारत में भी अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा वक्त की बात करें तो भारत फिलहाल अपनी कुल जरूरत का करीब 85 फीसदी आयात करता है। इसी के साथ हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आयातक देश हैं। फिलहाल, असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल का उत्पादन करता है। इसके अलावा भी कई राज्यों में भी तेल का भंडार पाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था में 20 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान दे सकती है, जिससे जीडीपी 5 गुना बढ़ सकती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रंजीत राठ ने कहा कि तेल की कीमतों में स्थिरता अन्वेषण प्रयासों की योजना बनाने में मदद करती है। **10पर**

सर्साफ़ा बाज़ार



(24 कैरेट गोल्ड)

सोना : 1,02,080/-  
(प्रति 10 ग्राम)

चाँदी : 1,12,150/-  
(प्रति किलोग्राम)

मौसम बेंगलूरू

अधिकतम : 30°

न्यूनतम : 21°

पूरे विश्व को परेशान कर रही एक और खतरे की आशंका

तेहरान, 17 जून (एजेंसियां)। इजराइल और ईरान के बीच तेज होते जा रहे संघर्ष के दरम्यान पूरे विश्व को एक और खतरे की आशंका परेशान कर रही है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किया तो पूरी दुनिया में तेल का भारी अकाल पड़ जाएगा। होर्मुज जलडमरूमध्य से काफी बड़ी मात्रा में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो दुनियाभर के कई देशों को इसका नुकसान झेलना

पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तेल के आवागमन के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते काफी कम और खर्चीले हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जल डमरू मध्य) वाले रास्ते को बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनियाभर के लिए काफी महत्वपूर्ण रास्ता है। स्ट्रेट



पूरी दुनिया में तेल की हो जाएगी भारी किल्लत

ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह

इतना गहरा और चौड़ा है कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकर्स को भी आराम से संभाल सकता है। इसके साथ ही यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक-पॉइंट्स में भी शामिल है। इस रास्ते से काफी बड़ी मात्रा में तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो दुनियाभर के कई देशों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तेल के लिए रास्ते से परे

अन्य वैकल्पिक रास्ते काफी कम और काफी लंबे एवं खर्चीले हैं। अगर किसी एक चेक-प्वाइंट से दूसरे तक के बीच कोई भी परेशानी होती है तो सबसे पहले आपूर्ति में देरी होगी। इसके चलते शिपिंग की लागत बढ़ेगी और अंततः वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा बहरीन के मनामा में रहकर जल डमरू मध्य की निगरानी करता है। **10पर**

कार्टून कॉर्नर







# ट्रेन सेवाओं और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए महाप्रबंधक से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन

हुब्बल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो।

दक्षिण पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति सदस्य (जेडआरयूसीसी) महेंद्र सिंघी और बेंगलूरु मंडल सलाहकार समिति सदस्य आश्विन सेमलानी ने दक्षिण पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक मुकुल शरण से रेल सौधा में मुलाकात कर ट्रेन सेव-1ओं और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए ज्ञापन सौंपा। ट्रेन संख्या 17317/17318 (हुब्बल्ली-दादर एक्सप्रेस) और 17319/17320 हुब्बल्ली-हैदराबाद एक्सप्रेस के कोच बढ़ाने का आग्रह किया। दोनों ट्रेनें वर्तमान में केवल 15 कोचों के साथ संचालित होती हैं, जो उच्च मांग को देखते हुए अपर्याप्त हैं। सीमित क्षमता के कारण यात्रियों को कन्फर्म टिकट प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ट्रेन संख्या 17317/17318 को दादर से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक बढ़ाकर इसको 24 कोचों के साथ संचालित किया जाए तो इस मार्ग



पर चलने वाले यात्रियों को बहुत आसानी होगी। साथ ही कुछ दिनों पहले हटाए गए फर्स्ट एसी कोच को पुनः जोड़ा जाए तो यात्रियों को सुविधा होगी। सदस्यों ने ट्रेन संख्या 16508 बेंगलूरु-जोधपुर एक्सप्रेस को दैनिक सेवा में परिवर्तित करने का आग्रह करते हुए कहा कि लगातार यात्रियों की उच्च मांग को

देखते हुए इस ट्रेन की आवृत्ति को दैनिक कर दिया जाए तो बेंगलूरु और जोधपुर के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। जिससे नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और यात्रा में आसानी होगी। ट्रेन संख्या 16209/16210 (बेंगलूरु-अजमेर एक्सप्रेस) के लिए जवाई

बांध स्टेशन (पाली जिला) जो की उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्र में आता है वहां पर अतिरिक्त ठहराव निर्धारित कर गोडवाड़ क्षेत्र पाली जिले और आसपास के क्षेत्रों के काफी संख्या में यात्रियों को जवाई बांध स्टेशन पर निर्धारित ठहराव से लाभ होगा। यह अतिरिक्त ठहराव क्षेत्रीय पहुंच

को मजबूत करेगा और लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक मांग को पूरा करेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत, जिसे कोविड -19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था, कृपया उसे पुनः शुरू की जाए। इस सुविधा को पुनः बहाल किया जाए तो बुजुर्ग यात्रियों के प्रति दयालुता होगी जो सुरक्षित और सस्ती यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर हैं। सदस्यों ने बेंगलूरु से मुंबई के लिए हुब्बल्ली के रास्ते स्लीपर वंदे भारत/सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का आग्रह किया। महाप्रबंधक मुकुल शरण ने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों और सुझावों को पूरा करने के लिए एसडब्ल्यूआर द्वारा गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

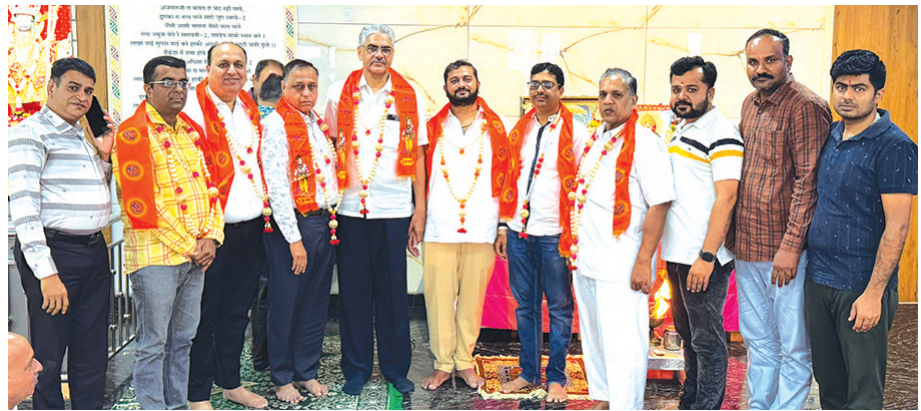
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रवासी ट्रेवेलर्स एसोसिएशन कर्नाटक के राज्य कार्यदर्शी सुभाष चंद्रा डंक, तनिश ललवानी सहित अन्य उपस्थित थे।

# जेपीएफ बेंगलूरु साउथ की नॉलेज सीरीज की शुरुआत

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। जीतो बेंगलूरु साउथ चैप्टर फाउंडेशन और जीतो प्रोफेशनल फोरम (जेपीएफ) के तहत अपनी नॉलेज सीरीज का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। इस ऑनलाइन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में स्टेबल मनी के संस्थापक सौरभ जैन ने भाग लिया। जेपीएफ नॉलेज सीरीज एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य व्यवसाय, प्रोफेशनल और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। रविवार को शुरू हुई और 15 सितंबर, 2026 को समाप्त होने वाली इस सीरीज में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि, चर्चा और ज्ञान साझा किया जाएगा। प्रत्येक महीने एक नया विषय अन्वेषण किया जाएगा, जिससे सीखने, नव-िचार और नेटवर्किंग के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम का संचालन तरुण कुमार बागमार ने किया और डॉ. अक्षय वी. खानटर ने इसकी मेजबानी की। इस ऑनलाइन सत्र में 130 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो सौरभ जैन के कॉर्पोरेट नेतृत्व और उद्यमिता के व्यापक अनुभव से सीखने के लिए उत्सुक थे। सत्र की शुरुआत नवकार मंत्र के पाठ के साथ हुई, जिसने एक प्रबुद्ध चर्चा के लिए स्वर निर्धारित किया। जेपीएफ बेंगलूरु साउथ के संयोजक रौनक गुलेचा ने सत्र में भाग लेने वालों का स्वागत किया और ज्ञान साझा करने और समाज निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. अक्षय वी. खानटर और सौरभ जैन के बीच आकर्षक बातचीत में उनके पेशेवर सफर के विभिन्न पहलुओं को शामिल

किया गया, जिसमें स्विगी में उपाध्यक्ष और नवी म्यूचुअल फंड में एमडी और सीईओ के रूप में उनकी भूमिका शामिल है। सत्र का मुख्य आकर्षण रैपिड-फायर सेगमेंट था, जहां उन्होंने स्टार्ट-अप, वित्त और उद्यमिता पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और पार करने के लिए व्यवसाय मालिकों के हाथों में होने के महत्व पर जोर दिया। जीतो बेंगलूरु साउथ के चेयरमैन रणजीत सोलंकी ने एक संदेश में जेपीएफ बेंगलूरु टीम की इस नॉलेज सीरीज को शुरू करने के लिए प्रशंसा कर कहा कि यह पहल ज्ञान और विश-षज्ञता के साथ हमारे समाज को शक्ति बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम भविष्य में और अधिक आकर्षक सत्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सत्र का समापन जेपीएफ बेंगलूरु साउथ समिति के चेयरमैन हरि किशन पी. छज्जर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। जेपीएफ नॉलेज सीरीज का उद्देश्य ज्ञान साझा करने, नेटवर्किंग और विकास के लिए एक मंच प्रदान करना है, जो जीतो समुदाय की विविध रुचियों और जरूरतों को पूरा करता है। अपनी सफल शुरुआत के साथ, यह सीरीज जेपीएफ बेंगलूरु के सीखने और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जीतो बेंगलूरु साउथ चैप्टर और गतिशील संगठन है जो समाज के विकास, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित है।

# मदारिया जैन ओसवाल साजनान संघ के पदाधिकारियों का सम्मान



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मदारिया जैन ओसवाल साजनान संघ, बेंगलूरु के अध्यक्ष ललित मंडोत एवं मंत्रिमंडल टीम अग्रहारा दामरहल्ली स्थित श्री बाबा रामदेव भक्त मंडली भवन अपनी संगठन यात्रा के तहत पहुंची।

भक्त मंडली के अध्यक्ष चेतन सिरवी ने सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता जताई कि जैन समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था का

आज बाबा रामदेव भक्त मंडली भवन पर पधारना हुआ कार्यक्रम हनुमान चालीसा द्वारा शुरू हुआ। पंडित राकेश उपाध्याय द्वारा सुमधुर भजन मंडली आयोजित हुई।

श्रीराम एवं हनुमान के भक्ति गीतों से पूरा हाल उत्सर्ग हो उठा। मदारिया जैन ओसवाल साजनान संघ के अध्यक्ष ललित मंडोत ने मंडली के प्रति आभार व्यक्त करते हुए व्यवस्था की सराहना की।

सभी से निवेदन किया कि भले सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो, सभी मिलकर साथ रहें। मंडली ने मदारिया जैन संघ के पदाधिकारी का सम्मान किया।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष रमेश दक, मंत्री सुरेश गत्रा, संगठन मंत्री प्रवीण दक, प्रचार प्रसार मंत्री प्रवीण बोहरा, प्रभारी रमेश चावत, सह प्रभारी भीकमचंद भटेवरा सहित क्षेत्र के वरिष्ठ एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।

# कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है: डा. प्रतिभा जैन श्री कांठा प्रांत जैन ट्रस्ट द्वारा करियर नेविगेटर कार्यक्रम का आयोजन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, इसलिये जब करियर की बात आती है तो हम सभी के लिये यह समझना और उचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यह तो निश्चित है कि सफलता का कोई शोर्ट कट नहीं होता है, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलती है।

यह बात श्री कांठा प्रांत जैन ट्रस्ट बेंगलूरु द्वारा युवाओं के लिये आयोजित कार्यक्रम करियर नेविगेटर कार्यक्रम में शिक्षा परामर्शदाता व प्रशिक्षक मुंबई की डा. प्रतिभा जैन ने कही। भारत भर में बसे कांठा प्रांतीय स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों के लिये व्यक्तिगत कौशल, रुचियों और लक्ष्यों पर परामर्श आधारित इस कार्यक्रम का आयोजन जूम पर किया गया। करियर



काउंसलिंग के इस सत्र में उभरते और अंतःविषय जैसे रोबोटिक्स और मेकट्रोनिक्समैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान को अत्याधुनिक स्वचालन और रोबोटिक्स अनुप्रयोगों के लिए संयोजित करना, एआई-संचालित अंतर्दृष्टिडेटा विज्ञान, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाले करियर पथ उद्योगों में बेहतर निर्णय लेने को

बढ़ावा देने जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया। आयोजन के संयोजक संजय गुंदेचा एवं सह संयोजक शुभम कोठारी के अनुसार डा. प्रतिभा जैन ने नए युग के करियर में बढ़ते क्षेत्र मसलन फिनेटेक, वित्त, प्रौद्योगिकी इत्यादि पर विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन दिया। डॉ. जैन ने भौतिकी और गणित अनुप्रयोग, ऐसे करियर जो मात्रात्मक वित्त, बीमांकिक

विज्ञान और डेटा विश्लेषण जैसे डोमेन में मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल का लाभ उठाते हैं, को भी समझाया। उन्होंने मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञानचिकित्सा, मानव संसाधन, विपणन और शिक्षा में अनुप्रयोगों के साथ मानव व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विज्ञान की खोज करने वाले मार्गों का परामर्श दिया।

साथ ही उन्होंने कुछ पाठ्यक्रमों पर चर्चा की जिनमें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज व्यवसाय और प्रबंधन-केंद्रित स्नातक डिग्री, बीबीए एलएलबी कॉर्पोरेट कानून और नीति में करियर के लिए आदर्श एकीकृत कानून और व्यवसाय पाठ्यक्रम, अन्य विचारित धाराएं, डिजाइन, लिबरल आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रम सम्मिलित थे।

कार्यक्रम के दौरान उत्साही विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान भी उन्होंने दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत मंगला-चरण से हुई। कांठा ट्रस्ट के अध्यक्ष उत्तमचंद कोठारी ने सभी का स्वागत करते हुए आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। महामंत्री सिद्धार्थ बोहरा ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को करियर पथ और विकास के क्षेत्रों की सिफारिश करने के लिए एआई संचालित अंतर्दृष्टि दी गई तथा फ्रेशर्स के बीच अनिश्चितताओं को दूर किया गया तथा प्रतिभागियों की असमंजसता को अपस्किंग तकनीकों पर चर्चा से दूर किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कांठा प्रांतीय विद्यार्थियों ने भाग लिया। संचालन सह संयोजक शुभम कोठारी ने किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव संयोजक संजय गुंदेचा ने व्यक्त किया।

# वनवासी राम सामाजिक समरसता के प्रतीक : जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज

समस्त भू-भाग उनकी मित्रता के सूत्र में बंध गया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

श्री राम परिवार दुर्गा पूजा समिति बेंगलूरु द्वारा शहर के पैलेस ग्राउण्ड स्थित प्रिंसेस श्रान में आयोजित नौदिवसीय श्री राम कथा में सोमवार को जगद्गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि वनवास काल में प्रभु श्रीराम उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहाँ भी गए वहाँ का समस्त भू-भाग उनकी मित्रता के सूत्र में बंध गया था। वे अपने मनुष्य धर्म से ऊपर उठकर कर्म का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आदर्श व्यक्तित्व के कारण ईश्वर बन गए। दीन हीन और उपेक्षितों को सच्चे मन से अपनाया, वन भ्रमण के समय केवट को गले लगाया। पक्षीराज जटायु को पिता का सम्मान दिया, भाल-बंदरों को आत्मीय बनाया। शबरी के जूठे बेर खाए, अहिल्या और शबरी जैसी नारियों का उत्थान किया। उन्होंने किसी का भी कभी तिरस्कार नहीं किया। शत्रु रावण को भी तिरस्कृत नहीं किया। इसीलिए वे समस्त मानव जाति के मन में अजात शत्रु रहे। इसी व्यक्तित्व वैशिष्ट्य के कारण श्रीराम के चौदह वर्षों के वनवास ने श्रीराम को रामत्व प्रदान किया। श्री राम कथा की समस्त जीवन



शैली, सामाजिक समरसता, वसुधैव कुटुम्बकम् का ज्ञान और श्री राम की आदर्श जीवन शैली ने उन्हें कोटि कोटि जन मन का कंठहार बना दिया। श्री राम को भगवान का दर्जा वनवासियों के बीच रहने के कारण ही मिला। उनका पूरा जीवन सामाजिक समरसता का सर्वोत्तम उदाहरण है। चाहे निषाद राज से मित्रता कर उन्हें बराबरी का स्तर देने या शबरी के झूठे बेर खाने या अहिल्या के उद्धार या फिर जटायु को सम्मान देने की कथा या फिर बहुत सी वनवासी प्रजातियों को बराबरी का दर्जा दिलाना प्रभु श्री राम का पूरा जीवन शोषित, वंचितएवं पीड़ित समाज के लोगों का कल्याण करने में बीता। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए कथाव्यास संत रामभद्राचार्य ने कहा कि चित्रकूट में वनवास के लगभग बारह वर्ष बिताने के बाद

प्रभु श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साथ दण्डकारण्य की ओर बढ़े। दंडकवन क्षेत्र में प्रभु श्रीराम ने पंचवटी कुटिया का निर्माण किया। यहीं रावण की बहन सूर्यपंखा वनवासी श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर जाती है। लेकिन राम उससे विवाह करने से इनकार कर देते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। जब लक्ष्मण भी विवाह करने से मना करते हैं तो वह क्रोधित हो जाती है। लक्ष्मण उसके नाक-कान काट देते हैं। सूर्यपंखा से इस घटना की खबर मिलने पर रावण अपने मामा मारीच को सोने का मृग बनाकर भेजता है। माता सीता उसे सोने के मृग को देखकर प्रभु श्रीराम से उसे पकड़ने को कहती हैं। प्रभु श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण को सीता की देखभाल करने को कहकर हिरण को पकड़ने जाते हैं। कुछ दूर जाकर

मायावी मृग बने मारीच ने प्रभु श्रीराम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण कहकर पुकारा। सीता यह पुकार सुन लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती हैं। लक्ष्मण पहले तो मना करते हैं किन्तु बाद में माता सीता के जोर देने पर चले जाते हैं। लेकिन जाते समय कुटी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच कर माता सीता को उससे बाहर न जाने के लिए कहकर जाते हैं। तभी रावण साधु का छद्मभेष धरकर वहाँ आता है और सीता का अपहरण कर ले जाता है। मार्ग में रावण को बलात् एक स्त्री को विमान ले जाते देख कर जटायु ने उसका विरोध किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ और पक्षीराज जटायु घायल हो गये। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण वहाँ पहुँचते हैं। घायल जटायु उन्हें रावण द्वारा सीता को आकाशमार्ग से लेकर

जाने के बारे में बताते हैं। वह राम को शबरी से जाकर मिलने को कहते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। प्रभु श्री राम जटायु की अंत्येष्टि करने के बाद शबरी के आश्रम पहुँचते हैं। जहाँ वर्षों से अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही शबरी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर आनन्द से भावविभोर हो जाती है और उन्हें चख चख कर जूठे बेर खिलाती है। प्रभु श्री राम प्रेमपूर्वक जूठे बेर खाते हैं। कथाव्यास जगद्गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचन्द्रदास ने मंगला-चरण किया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के. एस. ईश्वराप्पा तथा मुख्य यजमान जसराम महेन्द्र कुमार वैष्णव के साथ मिथिलेश तिवारी, राजू सुथार, अजय पाण्डेय आदि ने कथा पूजन में भाग लिया। यजमानों के साथ सभी लोग आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री राम परिवार के संस्थापक संजय शुक्ला, अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, कोषाध्यक्ष राजेश द्विवेदी, सहसचिव राजू शुक्ला तथा एकल शरीहर वनवासी फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार मोदी, सचिव संजय अग्रवाल सहित विभिन्न समाजों के अनेक अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। यह जानकारी सचिव अजय प्रकाश पाण्डेय ने दी।

# स्कूल में बच्चों के लिए डेस्क उपलब्ध करवाया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

तेरापंथ युवक परिषद् राजराजेश्वरी नगर ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए पट्टनोरे स्थित गवर्नमेंट लोवर प्राइमरी स्कूल में हनुमानमल, संजय, मनोज बैद नोखा बेंगलूरु के सहयोग से बच्चों के लिए डेस्क उपलब्ध करवाया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सामूहिक नमस्कार महामंत्र के संगाने से साथ किया। अध्यक्ष बिकाश छाजेड़ ने सभी का स्वागत किया और बताया कि तेयुप आर आर नगर हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहती है। आगे भी



आर स्कूल में कभी किसी प्रकार की जरूरत हो तो आप हमें याद करें। प्रायोजक परिवार से हनुमानमल ने कहा कि उन्हें इस तरह के सेवा कार्य करके बहुत प्रसन्नता होती है। स्कूल प्राध्यापक सुगुणा ने उनकी जरूरत पर डेस्क

उपलब्ध करवाने के लिए तेयुप आर आर नगर का धन्यवाद किया। इस अवसर पर परिषद् से प्रबुद्ध विचारक सुशील भंसाली, सेवा कार्य प्रभारी सौरभ चोड़िया, कार्यसमिति सदस्य समीक दुगड़ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। रमाबाई राज्य महिला संघ द्वारा विवेकानंद नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जरूरतमंदों में कंबल वितरित किए। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।



## बेंगलूरु में भगदड़ में मौतें

# इस्तीफे की मांग को लेकर सीएम के आवास का घेराव करने की कोशिश, कई भाजपा नेता हिरासत में

यह सरकार भगदड़ में मारे गए युवाओं के माता-पिता के अभिशाप के कारण गिरेगी



**बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।**  
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सरकारी आवास का घेराव करने की कोशिश करने पर बेंगलूरु में पुलिस ने कई भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया। वे 4 जून को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान शहर में मची भगदड़ के सिलसिले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता

चलवाडी नारायणस्वामी और पूर्व उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण शामिल हैं। नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को उस समय हिरासत में लिया गया, जब वे फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की ओर मार्च करने लगे। इससे पहले, प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, विजयेंद्र और अशोक ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पद छोड़ने तक अपना अभियान बंद न करने का आह्वान किया। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने आरसीबी की आईपीएल जीत को भुनाने के लिए मुख्यमंत्री के कहने पर जल्दबाजी में

विधान सौधा के सामने अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। उपमुख्यमंत्री ने चित्रास्वामी स्टेडियम में आयोजित समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मुख्यमंत्री को चकमा देने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक खींचतान के कारण पुलिस की सलाह के खिलाफ जल्दबाजी में विजय समारोह आयोजित किया गया। अशोक ने मुख्यमंत्री पर भगदड़ के लिए 'मुख्य दोषी' होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सिद्धरामैया अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठा दावा कर रहे हैं कि अभिनंदन समारोह सरकार द्वारा

आयोजित नहीं किया गया था और उन्हें नहीं पता कि राज्यपाल थावरचंद गहलोट को कार्यक्रम में किसने आमंत्रित किया था। लेकिन, यह पता चला है कि डीपीएआर और मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान की थी और मुख्यमंत्री ने खुद राज्यपाल को आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा सेल्फी लेने वाले लोग सीएम और अन्य राजनेताओं के रिश्तेदार थे, लेकिन निर्लंबित होने वाले पुलिस अधिकारी थे। अशोक ने कहा हमने कर्नाटक में पहले भी किसानों के अभिशाप के कारण सरकारें गिरते देखी हैं। यह सरकार भगदड़ में मारे गए युवाओं के माता-पिता के अभिशाप के

कारण गिरेगी। नारायणस्वामी ने आरोप लगाया लोग कह रहे हैं कि खुफिया विफलता थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस खुफिया प्रमुख के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से परहेज किया है, उन्हें स्थानांतरित करने के अलावा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई उनकी (सीएम) कुर्सी को छीन सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि तत्कालीन खुफिया प्रमुख की पत्नी एक कांग्रेस नेता हैं। इस मौके पर विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक डोड्डानगौड़ा एच. पाटिल, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण, पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद गोविंद करजोल,

सांसद पी.सी. मोहन, विधान परिषद विपक्ष के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक बसवराज, पूर्व मंत्री और विधायक के. गोपालैया, विधायक एल. रविसुब्रमण्यम, उदय गरुडचार, एस. मुनिराजू, एम. कृष्णप्पा, विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद, भारती शेटी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक धीरज मुनिराजू, बेंगलूरु दक्षिण जिला अध्यक्ष और विधायक सी.के. रामभूति, बेंगलूरु उत्तर जिला अध्यक्ष एस. हरीश, बेंगलूरु मध्य जिला अध्यक्ष ससगिरी गौड़ा, राज्य पदाधिकारी और पार्टी नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## भारी बारिश से जलाशयों में जलस्तर बढ़ा

आज से बारिश में  
कमी आएगी

**बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।**  
पिछले 8-10 दिनों से तटीय और मलनाड समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हो रही मानसूनी बारिश अगले दो दिनों तक जारी रहेगी। हालांकि, बुधवार से बारिश में कमी आने का अनुमान है। मानसून के फिर से सक्रिय होने से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और जलाशयों में पानी का बहाव बढ़ गया है। झरने जीवंत हो उठे हैं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। कृष्णा और कावेरी घाटियों की प्रमुख नदियों के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने मलनाड में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और जलाशयों के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अनुसार, उडुपी,



शिवमोगा, कोडागु, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, हावेरी, मैसूर और दावणगेरे जिलों में व्यापक वर्षा हुई है। करकला तालुक के पल्ली ग्राम पंचायत में 230 मिमी भारी वर्षा हुई। हासन जिले में मध्यम बारिश हुई, जबकि बेलगावी और धारवाड़ जिलों में छिटपुट बारिश हुई। राज्य के अन्य जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पनबिजली पैदा करने वाले लिंगनमकी, सुपा और

वाराही जलाशयों में कुल 74 हजार क्यूसेक अतिरिक्त पानी आया है। कावेरी घाटी के हरांगी और काबिनी जलाशयों में पानी आने से पानी का बहाव बढ़ा है। हरांगी जलाशय 72 फीसदी भरा है, जबकि काबिनी जलाशय 84 फीसदी भरा है। इन जलाशयों में मौजूदा पानी का बहाव 15 हजार क्यूसेक से अधिक है। हेमावती जलाशय, जो 70 फीसदी भरा है, में 8 हजार क्यूसेक पानी आया

है। इसी तरह केआरएस जलाशय, जिसकी भंडारण क्षमता 66 फीसदी है, में 16 हजार क्यूसेक से अधिक पानी आया है। चिक्कमगलूर, हासन, कोडागु और केरल में भारी बारिश के मद्देनजर जलाशयों में पानी का बहाव और बढ़ने की संभावना है। यदि आवक इसी तरह जारी रही तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि जून के अंत तक ये जलाशय पूरी तरह भर जाएंगे।

कृष्णा बेसिन के भद्रा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालाप्रभा, अलमट्टी, नारायणपुर जलाशयों में आवक बढ़ गई है। कुल मिलाकर इन जलाशयों में 60 हजार क्यूसेक से अधिक पानी बह रहा है। इन जलाशयों में 40 फीसदी पानी संग्रहित हो चुका है। पिछले साल इसी समय राज्य के प्रमुख जलाशयों में केवल 84.05 टीएमसी फीट पानी था। इस साल 174.66 टीएमसी फीट पानी संग्रहित हो चुका है। मई में मानसून शुरू होने पर भी इसी तरह भारी बारिश हुई थी। जलाशयों में पर्याप्त पानी था। कोंकण क्षेत्र में मेलई चक्रवात के कारण राज्य में आंशिक रूप से बादल छाप रहेगे, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगले दो दिनों तक तटीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। अंदरूनी इलाकों के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, केवल कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है।

## सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश

कचरा निपटान में समूह बनाकर बड़ा माफिया  
खड़ा कर दिया गया है: शिवकुमार

**बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।**

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कचरा निपटान में समूह बनाकर बड़ा माफिया खड़ा कर दिया गया है। सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार इसके आगे झुकने वाली नहीं है। वे सबको उखाड़ फेंकेंगे और नए अवसर पैदा करेंगे। पर्यावरण दिवस समारोह के तहत विधान सौधा के निकट रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर में कचरा निपटान व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। पहले 89 टेंडर हुए थे। जब दोबारा टेंडर करने का फैसला हुआ तो सभी लोग एक समूह में कोर्ट चले गए। स्टे ऑर्डर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने इस बात पर असंतोष जताया कि कचरा निपटान में बड़ा माफिया खड़ा है। उन्हें लगता है कि सरकार के दोबारा टेंडर से बचा जा सकता है। हम कोर्ट को



मना लेंगे। वे कोई भी काम करें, वे जनहित याचिका दायर कर उसमें बाधा डाल रहे हैं। हमारी सरकार में इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी बाधा डाल रहा है, उसे हटाया जाएगा। आईपीएल जीत के जश्न के दौरान चित्रास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ पर भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास भाजपा सरकार में हुई घटनाओं और उससे हुई जानमाल की लंबी सूची है। भाजपा शव पर राजनीति कर रही है। भगदड़ मामले में दोषियों को सजा मिल चुकी है। आगे की जांच के लिए माइकल कुन्हा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। उनके खिलाफ कई साजिशें रची

गई हैं। उन्होंने कहा कि विल्टलनाहल्ली मामला और गंगाधर हत्याकांड समेत कई मामलों में क्या हुआ, उन्हें पता है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि दूसरे राज्यों में भगदड़ जैसी कितनी घटनाएं हुई हैं, खासकर उन जगहों पर जहां भाजपा सत्ता में है। भाजपा चाहे जितनी भी राजनीति कर ले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2028 में फिर से विधानसभा में सत्ता संभालेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मुख्यमंत्री का पदभार स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा जैसे-जैसे कोई बड़ा होता है, वैसे-वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा मुझे निशाना बना रही है और राजनीति कर रही है।

## सुनील कुमार ने सीएम के इस्तीफे और विशेष सत्र की मांग की



**बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।**  
विधायक और भाजपा के प्रदेश महासचिव वी. सुनील कुमार ने मांग की है कि आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ और 11 लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस मामले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। यहां

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने की घोषणा करके भगदड़ में 11 निर्दोष युवकों की मौत पर चर्चा को भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह शर्मनाक मामला है। उन्होंने बताया कि हमने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध जारी रखा है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने जश्न

में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से भाग लिया। उन्होंने कहा कि विधान सौधा में एक, एयरपोर्ट पर एक और स्टेडियम में एक जैसी प्रतिस्पर्धा थी। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है जहां वे यह कहकर दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।

## ईडी ने ऐश्वर्या गौड़ा धोखाधड़ी मामले में डी के सुरेश को किया तलब

**बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।**

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के छोटे भाई कांग्रेस नेता डी के सुरेश को एक स्थानीय महिला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्व सांसद सुरेश को 19 जून को पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। संघीय जांच एजेंसी ने स्थानीय महिला - 33 वर्षीय ऐश्वर्या गौड़ा - को उसके और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ छापेमारी के बाद अप्रैल में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि



महिला ने कई हाई-प्रोफाइल राजनेताओं के साथ निकटता का दावा किया और लोगों को सोने, नकदी और बैंक जमा पर उच्च रिटर्न का वादा करके धोखा दिया। उस पर आरोप है कि उसने सुरेश के नाम का इस्तेमाल किया और उसकी बहन होने का दावा किया। सुरेश ने बेंगलूरु पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके नाम का 'दुरुपयोग' किया जा रहा है। समझा जाता है कि ईडी ने जांच के तहत कुलकर्णी का बयान दर्ज किया है। गौड़ा और उनके पति हरीश केएन के अलावा अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर से उपजा है।

## युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कन्नड़ लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी: सीएम

**बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।**

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि विदेशों में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कन्नड़ लोगों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों के साथ लगातार संपर्क में है। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा मैंने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कन्नड़ लोगों से बात की है। मैंने हमारे कांग्रेस नेता नटराज गौड़ा से भी बात की है। वहां हवाई अड्डे फिलहाल बंद हैं, लेकिन लोगों की उचित देखभाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि



राज्य सरकार केंद्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है और स्थिति में सुधार होते ही फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। बुधवार या गुस्वार को हवाई अड्डे के फिर से खुलने की संभावना है। सिद्धरामैया ने प्रभावित परिवारों

को आश्वासित करते हुए कहा ऐसा होने पर हम उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अधिकारी यात्रा का समन्वय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि फंसे हुए व्यक्तियों की वापसी सुचारु रूप से और तत्-परता से हो।





# फिल्मों की स्क्रीनिंग में आगजनी और हिंसा की धमकी नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

## फिल्में रिलीज करने के अधिकार को बरकरार रखा

बेंगलूरु/नई दिल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म निर्माताओं और थिएटर मालिकों के बिना आगजनी और हिंसा की धमकी के फिल्में रिलीज करने के अधिकार को बरकरार रखा। साथ ही यह स्पष्ट किया कि कर्नाटक सरकार को कमल हासन के राज्य में 'ठग लाइफ' की स्क्रीनिंग के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति मनमोहन की एक अवकाश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने कर्नाटक सरकार के पक्ष को संबोधित करते हुए कहा हम भीड़ और निगरानी समूहों को अपनी सड़कों पर कब्जा करने नहीं दे सकते। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। कानून का शासन कायम रहना चाहिए। पीठ बेंगलूरु निवासी एम. महेश रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एथेनम वेलन कर रहे थे, जिसमें कर्नाटक में हासन की सीबीएफसी-प्रमाणित तमिल फिल्म की सुरक्षित और निर्बाध स्क्रीनिंग सुनिश्चित



करने की मांग की गई थी। याचिका में उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई थी, जिन्होंने सिनेमाघरों और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ धमकियां दी हैं और हिंसा भड़काई है। कानून के नियम की मांग है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी फिल्म रिलीज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिल्म निर्माता इस बात से परेशान नहीं हो सकते या उन्हें डर नहीं होना चाहिए कि फिल्म दिखाने के लिए सिनेमाघरों को जला दिया जाएगा। लोग फिल्म देखने नहीं आ सकते। हम लोगों को फिल्म देखने आने का आदेश नहीं दे रहे। लेकिन फिल्म जरूर दिखाई जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि वह न केवल कानून के नियम के संरक्षक बल्कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका में इस मामले में दृढ़ता से हस्तक्षेप करेगा। कानून के नियम के अनुसार आप किसी फिल्म की रिलीज को नहीं रोक सकते। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि सीबीएफसी प्रमाण पत्र मिलने के बाद फिल्म रिलीज हो। हम इसी कानून का पालन करते हैं। लोग फिल्म देखने नहीं आ सकते, लेकिन सिनेमाघरों में आगजनी और घेराव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़े नहीं आ सकते। न्यायमूर्ति भुयान ने 1990 के दशक में मराठी नाटक 'मी नाथूराम गोडसे बोल-

तोय' के मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति भुयान ने अदालत में कहा इसमें राष्ट्रपिता के अलावा किसी और के बारे में आलोचनात्मक संदर्भ नहीं थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग दृष्टिकोण रखने के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबंध को अलग रखा।

न्यायाधीश ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को आपराधिक अभियोजन से दी गई सुरक्षा का भी उल्लेख किया। सांसद सोशल मीडिया पर अपनी कविता पोस्ट करने के लिए एफआईआर का सामना कर रहे थे। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा अगर कोई बयान देता है तो उस पर बहस होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ होगी जिसमें एक व्यक्ति बयान देता है और हर कोई उसे सत्य मान लेता है। वेलन ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के न्यायिक संरक्षण की मांग करने वाली कार्यवाही में तृष्टिकरण को प्राथमिकता दी है। अवैध धमकियों को रोकने और प्रमाणित फिल्म के प्रदर्शन

की सुरक्षा के लिए राज्य को स्पष्ट निर्देश देने के बजाय - जो कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए मौलिक है - चर्चा कथित तौर पर इस बात पर केंद्रित थी कि क्या कमल हासन को उन्हें डराने और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाले अतिवादी तत्वों से माफी मांगनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि अपराधियों के साथ समझौता करने का सुझाव देकर बलपूर्वक सेंसरशिप का यह प्रभावी समर्थन न्याय प्राप्त करने के लिए वर्तमान में उच्च न्यायालय के मार्ग को अप्रभावी बनाता है, जिससे संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में यह तत्काल अपील करने की आवश्यकता पड़ती है। याचिका में राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में कर्नाटक सरकार की घोर विफलता पर सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक में असंवैधानिक न्यायेतर प्रतिबंध किसी वैध प्रक्रिया से नहीं बल्कि आतंक के जानबूझकर चलाए गए अभियान और पिछले तमिल विरोधी दंगों को दोहराने के लिए एक भयावह आह्वान से उपजा है।

## बस से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, सवार की मौत



उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो। जिले के हेमडी-कोल्लूर मुख्य मार्ग पर केंचनूर के मल्लारी मोड़ के पास एक निजी बस से बाइक टकराने से सिगंदूर निवासी 25 वर्षीय बाइक सवार शरत की मौके पर ही मौत हो गई। निजी बस हेमडी से कोल्लूर की ओर जा रही थी, तभी तेज रफ्तार बाइक उससे टकरा गई। सड़क पर गिरने से शरत के सिर और बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत एंबुलेंस से कुंडापुर सरकारी

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

टक्कर के कारण ड्यूक बाइक के रेडिएटर पर पेट्रोल गिर गया, जिससे उसमें आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई। शंकरनारायण थाने के सर्किल इंस्पेक्टर जयराम डी गौड़ा और कुंडापुर ट्रैफिक एसआई प्रसाद कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया। कुंडापुर ट्रैफिक थाने में मामला दर्ज किया गया है।

## दावणगेरे में 1,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत

## अगर मोदी को गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए प्यार नहीं, तो 56 इंच का सीना बेकार: सीएम

दावणगेरे/शुभ लाभ ब्यूरो।

दावणगेरे में 1,350 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि यह कदम भाजपा के उन आरोपों का जवाब है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन नहीं है। परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद दावणगेरे में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर उन्हें गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए प्यार और चिंता नहीं है, तो 56 इंच का सीना बेकार है। कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाएं भाजपा को दिखाई नहीं दे रही हैं। हम विकास को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, तो एक ही दिन में 1,350 करोड़ की विकास परियोजनाएं कैसे शुरू की जा सकती हैं?

सिद्धरामैया ने कहा कि न केवल बजट में वृद्धि हुई है, बल्कि जीएसटी संग्रह में कर्नाटक दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो



राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है। उन्होंने कहा भाजपा ने सत्ता में रहते हुए गरीबों को एक भी घर नहीं दिया। लेकिन हमने अकेले दावणगेरे जिले में 1,892 घर पौराकर्मिकाओं को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जातियों और समुदायों का वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की आकांक्षाओं के अनुसार सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है। उन्होंने बढ़ती कीमतों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एकमात्र कारण बताते हुए उग्र-स्थित लोगों से जानना चाहा कि क्या किसी ने मोदी के 'अच्छे दिन' देखे हैं। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में केंद्र द्वारा धन आवंटन के

मामले में कर्नाटक सरकार के साथ हुए अन्याय को सूचीबद्ध किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि उन्होंने केंद्र द्वारा कर्नाटक के साथ किए गए अन्याय के बारे में झूठ बोला होता, तो वे सार्वजनिक मंच से भाषण नहीं देते। उन्होंने भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक को राज्य में अर्थव्यवस्था और विकास पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और एस.एस. मल्लिकार्जुन, सांसद डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन और कई अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सहायता वितरित की।

## भाजपा को हमसे इस्तीफा मांगने का क्या नैतिक अधिकार

## मुख्यमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों में हुई मौतों के बाद इस्तीफा देने वाले नेताओं की सूची मांगी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी भाजपा को चुनौती दी कि वह भाजपा शासित राज्यों में हुई भगदड़ के बाद इस्तीफा देने वाले नेताओं की सूची जारी करे और फिर उनसे और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से इस्तीफा देने की मांग करे। 2002 में गुजरात दंगों, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, मणिपुर में हिंसा, गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना जिसमें 140 लोगों की जान चली गई थी और जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले के दौरान 30 तीर्थयात्रियों की मौत का हवाला देते हुए सिद्धरामैया ने भाजपा के विरोध और उनके तथा शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश 4 जून को बेंगलूरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की जांच कर रहे हैं जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ



बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेस को जारी एक बयान में, सिद्धरामैया ने कहा 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जो हुआ, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। एक जिम्मेदार सरकार के रूप में, हमने इस घटना की जवाबदेही ली है। हमने बेंगलूरु शहर के पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्लंबित कर दिया है और राज्य खुफिया विभाग के प्रमुख का तबादला कर दिया है। मेरे राजनीतिक सचिव (गोविंदराजू, एमएलसी) को भी उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, हमने मामले की गहन जांच करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जॉन माइकल डी'कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। भाजपा की राज्य इकाई

ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरामैया ने कहा ऐसी निर्णायक कार्रवाई करने के बावजूद कर्नाटक में भाजपा नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके इरादे लोगों के प्रति वास्तविक चिंता से प्रेरित होने के बजाय राजनीतिक हैं। त्रासदियों का राजनीतिकरण करना भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। हम हर त्रासदी से प्रभावित परिवारों के दुख और पीड़ा को साथ सहानुभूति रखते हैं। यही कारण है कि हम राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी घटनाओं का फायदा नहीं उठाते हैं। हालांकि, भाजपा नेताओं द्वारा इन घटनाओं को उछालकर जनता को भड़काने के बार-बार प्रयासों को देखते हुए, हम उनके शासन के दौरान हुई

कुछ घटनाओं को लोगों के ध्यान में लाकर उनके पाखंड को उजागर करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। सिद्धरामैया ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर में हुई मौतों को लेकर भाजपा से सवाल किए। उन्होंने पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहा 2002 में गुजरात दंगों के दौरान विभिन्न समुदायों के लगभग 2,000 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने के सुझाव के बावजूद, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो पद छोड़ा और न ही आज तक कोई खेद व्यक्त किया। इस वर्ष अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दौरान 26 लोगों की जान चली गई थी। हमारी पार्टी ने इस घटना पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की थी। हमने केवल हमले पर चर्चा के लिए एक विशेष संसद सत्र का अनुरोध किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया था। अभी भी, इस हमले के अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। क्या यह केंद्र सरकार की विफलता नहीं है? इस विफलता

के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सिद्धरामैया ने कहा पिछले दो सालों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह 20 महीने तक सत्ता में बने रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही इस्तीफा दिया, लेकिन राज्य में हिंसा जारी है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए?

गुजरात में मोरबी पुल ढहने से 140 लोगों की जान चली गई। इस साल जनवरी में उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले के दौरान 30 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा से नहीं थे? उन्होंने न केवल इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन सरकारों ने इन घटनाओं की उचित जांच भी नहीं की। ऐसे में भाजपा को हमसे इस्तीफा मांगने का क्या नैतिक अधिकार है? सिद्धरामैया ने कर्नाटक के भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे 'सड़क पर नाटक करना बंद करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करें।

# उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने स्वच्छता रैली की शुरुआत की

## साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने विधान सौधा के निकट विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता नम्मा नदीगे रैली को हरी झंडी दिखाकर खाना किया। रैली में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी, स्काउट्स कैप्स, आम जनता, अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डी.के. शिवकुमार ने विधान सौधा में साइकिल चलाकर रैली को खाना किया और साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कुछ दूर चलने के बाद डी.के. शिवकुमार ने साइकिल चलाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि वे भी स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्काउट्स गाइड कैप थे। पर्यावरण संरक्षण



में बच्चों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक प्रतिबंध को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण अनुकूल क्लब शुरू किए जा रहे हैं और 50 हजार से अधिक क्लब अस्तित्व में आ चुके हैं। बेंगलूरु में बारिश के कारण हो रही आ-पदाओं को लेकर चिंता जताने की जरूरत नहीं है। सरकार समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा

कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक बारिश जरूरी है। बाद में विधान सौधा के पूर्वी द्वार की सीढ़ियों पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डी.के. शिवकुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भावी जीवन के लिए जरूरी है। बेंगलूरु में विधान सौधा एक पवित्र स्थान है, जहां कानून बनते हैं और न्यायपालिका इसके सामने होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा डिजाइन दुनिया में कहीं नहीं मिलता।

विधान सौधा को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पर्यावरण को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसे बचाने के लिए हरित सांस के आदर्श वाक्य का पालन किया जाना चाहिए। बच्चों को पेड़ लगाने और प्रकृति की रक्षा में रुचि लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को इसमें अधिक सक्रियता से शामिल होना चाहिए। हर स्कूल में पर्यावरण क्लब होना चाहिए। आने वाले दिनों में इनके माध्यम से कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्ला-स्टिक को पूरी तरह से खत्म करना सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे, विधायक रिजवान अरशद, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी.एम. नरेंद्रस्वामी, विधान परिषद सदस्य सुदनदास, जैव ईंधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष एस.ई. सुधुन्दी एवं अन्य उपस्थित थे।

## पिता द्वारा फेंकी गई बीड़ी का टुकड़ा निगलने से 10 महीने के बच्चे की मौत

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

अड्यार से एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने घर के अंदर लापरवाही से बीड़ी का टूट फेंक दिया था। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले एक दंपति के बेटे अनीश कुमार के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई।

बच्चे को दोपहर करीब 3:30 बजे वेनलॉक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से रविवार सुबह 10:25 बजे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बच्चे की मौत पिता की लापरवाही के कारण हुई है। उसने कथित तौर पर पिता को कई बार चेतावनी दी थी कि वह घर के अंदर बीड़ी के टूट न फेंके, लेकिन उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ।

## कन्नूर भूस्खलन में 5 घर नष्ट, विधायक ने बुनियादी ढांचे के लिए 3 करोड़ की राहत की घोषणा की

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मेंगलूरु में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कन्नूर में, पास की पहाड़ी से भूस्खलन के कारण पांच घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमीद उस्ताद, मैमुना, सादिक और शेनाज सहित प्रभावित परिवार अब गंभीर स्थिति में हैं। मेंगलूरु दक्षिण के विधायक वेदव्यास कामथ ने कन्नूर वार्ड की पूर्व पार्षद चंद्रावती के साथ घटनास्थल का दौरा किया और नुकसान का आकलन किया।

प्रभावित निवासियों में से एक सादिक ने भयावह अनुभव को याद करते हुए कहा लगभग 3 बजे, भारी बारिश के कारण हमारे घरों के पीछे की पहाड़ी ढह गई। चूंकि बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पहाड़ी ढह गई। हर दिन हम पानी के बहने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन बारिश की तीव्रता के कारण भारी भूस्खलन हुआ,



जिससे पांच घर क्षतिग्रस्त हो गए। विधायक वेदव्यास कामथ ने कहा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कन्नूर के दयाम्बु गुड्डे में पांच घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कन्नूर में रेलवे ट्रैक के पास 100 से ज्यादा घर हैं, लेकिन उनमें उचित सड़क संपर्क नहीं है, जिससे निवासियों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।

मैं दयाम्बु गुड्डे में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अल्पसंख्यक कल्याण कोष से 3 करोड़ रुपये का उपयोग करने की योजना बना

रहा हूँ, जिसमें चार पहिया वाहनों के लिए उपयुक्त सड़कों भी शामिल हैं। चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान, निवासियों को मोटर योग्य सड़कों की कमी के कारण मरीजों को पैदल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम इस क्षेत्र में एक अंडरपास बनाने की भी योजना बना रहे हैं, और मैंने इस बारे में मंत्री वी सोमना से बात की है। इसके अतिरिक्त, एक नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और हम रेलवे विभाग से आवश्यक अनुमति लेंगे।









आजमगढ़ के मुस्लिम बहुल गांव में 40 दलित परिवार संकट में

# जय श्रीराम बोलने पर कट्टरपंथी मुस्लिमों ने मचाया तांडव

आजमगढ़, 17 जून (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटा पुरा के मुस्लिम बहुल इलाके में लगभग 40 हिंदू दलित परिवारों ने अपने घरों पर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और रेप की धमकी देने का आरोप लगाया है। यूपी के आजमगढ़ के मुस्लिम बहुल छोटा पुरा में करीब 40 दलित परिवारों ने अपने मकानों पर घर बिकाऊ है के बोर्ड लगा दिए हैं। इन लोगों ने खुद को असुरक्षित बताया है। बार-बार हो रहे उत्पीड़न, रेप की धमकी से ये लोग परेशान हैं और पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। 3 जून को स्थानीय मुस्लिम युवकों ने एक शादी समारोह के दौरान महिलाओं को परेशान किया था। इस दौरान मुस्लिम और दलित समुदाय के बीच मारपीट हुई है। इससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

दरअसल 3 जून 2025 को बम्हौर गांव के युवक राकेश कन्नौजिया की शादी थी। इस मौके पर दलित समुदाय की महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक विवाह-पूर्व की रस्में निभा रही थीं। उत्सव का माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब मुस्लिम समुदाय के कई युवक वहां पहुंच गए और महिलाओं की सहमति के बिना उनका वीडियो बनाने लगे। इस



पर आपत्ति जताने पर मुस्लिम युवकों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं से छेड़छाड़ किया। घबराकर महिलाओं ने मदद के लिए शोर मचाया, जिससे पुरुष रिश्तेदारों को बीच-बचाव करना पड़ा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

गांव के राकेश कन्नौजिया, बृजेश गोंड और रामअवध समेत कई दलित परिवारों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग धूम-धूमकर धमकी दे रहे हैं।

उन्होंने दावा है कि 3 जून की झड़प कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि उत्पीड़न का सिलसिला बहुत दिनों से जारी है। दलित परिवारों का आरोप है कि महीनों से उन्हें भक्ति गीत बजाने, शादियों में डीजे बजाने या सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि जय श्रीराम के नारे लगाने और त्योंहार मनाने में भी इन्हें दिक्कतों ता सामना करना पड़ता है।

दलित परिवारों का कहना है कि महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है और धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई तो वे लोग पलायन कर जाएंगे। एक दलित

व्यक्ति ने कहा, हमारी बेटियां और पत्नियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। त्योंहार खुशियों के बजाय तनावपूर्ण हो गए हैं। और जब हम शिकायत करते हैं, तो कुछ नहीं होता। एक अन्य दलित व्यक्ति ने कहा, हम कई बार पुलिस के पास गए। हमने बेहतर सुरक्षा और सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। इसलिए हमने अपने घर बेचने का फैसला किया है। कम से कम हम कहीं और शांति से रह सकते हैं।

आजमगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) मधुवन कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ऐसे परिवारों से सम्पर्क कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा, हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है कि कुछ परिवार पलायन करने की योजना बना रहे हैं। हम उनसे सम्पर्क कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। मुबारकपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी निहान नंदन ने भी कहा कि शांति बहाल करने के लिए 3 जून की घटना के बाद इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बावजूद अधिकांश परिवार आश्वस्त नहीं दिखते। दलित परिवारों का कहना है कि पहले यह सुरक्षा कहां थी? प्रशासन को जागने के लिए सुर्खियों और विरोध प्रदर्शनों की क्या जरूरत है?

## 75 जिलों में मूंग और 15 जिलों में मूंगफली खरीद शुरू

02 सितंबर तक खरीदी जाएगी मूंग, 29 अगस्त तक मूंगफली

लखनऊ, 17 जून (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों की आय बढ़ाने के लिए जायद सीजन में मूंग और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। यह खरीद सभी 75 जिलों में मूंग और 15 जिलों में मूंगफली के लिए की जा रही है, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को मुनाफा होगा। योगी सरकार मूंग की खरीद 02 सितंबर तक और मूंगफली की खरीद 29 अगस्त तक करेगी। खरीद मूल्य के रूप में मूंग के लिए 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली के लिए 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।

सरकार ने 34,720 मीट्रिक टन मूंग और 50,750 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत किसानों को क्रय केंद्रों पर अपनी उपज लाकर समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। नैफेड और एनसी-सीएफ को खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। जो राज्य एजेंसियां यूपीपीसीयू, यूपीपीसीएफ, जैफेड, यूपीएसएस द्वारा खरीद करेंगी। नैफेड 24,304 मीट्रिक टन मूंग और 35,525 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदेगा। वहीं एनसी-सीएफ 10,416 मीट्रिक टन मूंग और 15,225 मीट्रिक टन



मूंगफली खरीदेगा।

योगी सरकार ने मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए जिलावार क्रय केंद्रों का निर्धारण कर नैफेड और एनसीसीएफ को जिम्मेदारी सौंपी है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नैफेड उत्तर प्रदेश के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। यह अभियान किसानों को प्रोत्साहित करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगा। जिन जिलों में नैफेड मूंग खरीदेगा उनमें मथुरा, अलीगढ़, जालौन, आगरा, औरैया, ललितपुर, हाथरस, मैनपुरी, एटा, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर,

गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, मुजफ्फरनगर, अमरौहा, बलरामपुर, सहारनपुर और बिजनौर शामिल हैं। नैफेड जिन जिलों में मूंगफली खरीदेगा उनमें मैनपुरी, हरदोई और इटावा शामिल हैं। इसके अलावा, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, कोशाम्बी, प्रतापगढ़, हमीरपुर, कन्नौज, बुलंदशहर, कासगंज, शाहजहांपुर, चंदौली, सुल्तानपुर, बदायूं, रायबरेली, बलिया, हापुड़ और फर्रुखाबाद जिलों में एनसी-सीएफ मूंग और फर्रुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, कासगंज, औरैया, कानपुर देहात, बदायूं, एटा, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर नगर और श्रावस्ती जिले में मूंगफली खरीदेगा।

## एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी से दक्षिणांचल का होगा कार्याकल्प

गोरखपुर, 17 जून (एजेंसियां)।

जनपद के जिस दक्षिणांचल को सबसे पिछड़ा क्षेत्र मान लिया गया था, अब वह आगामी सालों में विकास और नई औद्योगिक पहचान की आभा से चहक उठेगा।

दक्षिणांचल के कार्याकल्प का आधार बनेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 20 जून को लोकार्पित होने जा रहा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे। लिंक एक्सप्रेस-वे की शानदार रोड कनेक्टिविटी के चलते योगी सरकार दक्षिणांचल के धुरियापार में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और देश की नामी कंपनियों को यहां उद्योग के लिए जमीन भी पसंद आने लगी है। अड़ानी सहित कई औद्योगिक घराने यहां निवेश के लिए तैयार हैं।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे गोरखपुर को केंद्रित कर पूर्वी यूपी की औद्योगिक प्रगति की इबारत लिखने के लिए सुनहरा पन्ना बन रहा है। खासकर गोरखपुर के दक्षिणी हिस्से के लिए। गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित है धुरियापार क्षेत्र। इस इलाके की जो जमीन ऊसर थी, जिसपर कोई फसल मुश्किल से उगती थी, वहां योगी सरकार उद्योगों की फसल लगवाने को तत्पर है। इसके लिए



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा 5500 एकड़ में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को मूर्त रूप दिया जा रहा है। करीब डेढ़ दर्जन गांवों की अनुपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण के सिलसिले में अब तक 600 एकड़ जमीन गीडा द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूर्वांचल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक वाली होगी। योगी सरकार की मंशा यहां बड़े उद्योगों का संजाल बिछाने के साथ इसे इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर के रूप में विकसित कर देने की है। इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे बैंक बोन का काम करेगा।

ऊसर धरती पर उद्योगों के जरिये रोजगार की भरपूर छांव मिले, योगी सरकार इसी फॉर्मूले के तहत ग्रेटर गीडा के रूप में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास कर रही है। मूर्त रूप में आने के बाद यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप धुरियापार समेत समूचे गोरखपुर दक्षिणांचल के लिए गेम चेंजर साबित होगी। धुरियापार की पहचान अति पिछड़े क्षेत्र के रूप

में रही लेकिन आने वाले दिनों में इसकी ख्याति गोरखपुर के नए औद्योगिक क्षेत्र के गेटवे के रूप में होगी। बीते आठ सालों में देश-दुनिया के कई निवेशकों का रुझान गोरखपुर की तरफ

देखते हुए सरकार धुरियापार क्षेत्र को ग्रेटर गीडा बनाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ ही यहां रोजगार की बहार भी बहेगी। गोरखपुर के दक्षिणांचल के औद्योगिक विकास को लेकर योगी सरकार काफी संजीदा है। धुरियापार में बनने के बाद से ही बंद पड़ी चीनी मिल के कुछ हिस्से में इंडियन ऑयल की तरफ से कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाया जा चुका है। इस प्लांट के बाद धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मूर्त रूप में आने के बाद इस क्षेत्र का कार्याकल्प हो जाएगा। इंडस्ट्रियल टाउनशिप में लगने वाले उद्योगों से करीब 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ होगा। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए निवेश प्रस्ताव आने शुरू भी हो गए हैं। अड़ानी समूह ने एसीसी ब्रांड के सीमेंट प्लांट के लिए जमीन की मांग की है। श्री सीमेंट और केयान डिस्टिलरी ने भी नया प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग की है। इसके अलावा कई अन्य औद्योगिक समूह यहां निवेश में रुचि दिखाई है।

लखनऊ, 17 जून (एजेंसियां)।

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। पावर कारपोरेशन ने संशोधन का जो प्रस्ताव भेजा है उसमें बिजली महंगी होने जा रही है। पावर कारपोरेशन की ओर से विद्युत नियामक आयोग में दाखिल बिजली दरों में 40-45 फीसदी बढ़ोतरी का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम फिक्स चार्ज 8 और शहरी के लिए 9 रुपए प्रति प्रति यूनिट हो जाएगा। उन्हें अधिकतम फिक्स चार्ज के साथ प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज, विद्युत कर और दूसरे शुल्क जोड़कर प्रति यूनिट 12 से 13 रुपए चुकाने होंगे।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया है कि पावर कारपोरेशन ने फिक्स चार्ज में बड़ा खेल किया है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को पावर कारपोरेशन की ओर से दिए प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को नियामक आयोग में लोकमहत्व प्रस्ताव दाखिल किया। नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय सिंह से मुलाकात कर प्रस्ताव को असांविधानिक करार देते हुए खारिज करने की मांग

की।

वर्मा ने बताया कि भाजपा के संकल्प पत्र में गरीबों को 100 यूनिट तक तीन रुपए प्रति यूनिट देने की बात कही गई है। उसे भी चार रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। पहले बिजली दरों के चार स्लैब थे, जिन्हें तीन कर दिया गया है। कुछ स्लैब में बिजली दरों में 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। इसे लौटाने पर कोई बात नहीं हो रही है। वर्मा ने बताया कि नए प्रस्ताव में फिक्स चार्ज भी बढ़ाया गया है। शहरी फिक्स चार्ज को 110 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में फिक्स चार्ज 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोवाट प्रस्तावित किया है।

बिजली के निजीकरण की चर्चा के बीच ही यूपी सरकार बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर 45 फीसदी और शहरी उपभोक्ताओं की 40 फीसदी बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव



दाखिल कर दिया है। जबकि सात जुलाई से बिजली दर निर्धारण के लिए सुनवाई की तिथि तय है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। साथ ही नियामक आयोग से इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है।

पावर कारपोरेशन ने बिजली कंपनियों की ओर से मई माह के पहले सप्ताह में वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) दाखिल किया। 19 मई को बिजली कंपनियों का घाटा 9200 से बढ़ाकर 19600 करोड़ दिखाते हुए 30 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। अब एक बार फिर शुक्रवार को गुप्तचुप तरीके से पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है।

प्रस्ताव में श्रेणीवार दरें बढ़ाने की मांग की गई है, जिसमें ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 40 से 45 फीसदी वृद्धि और घरेलू

शहरी उपभोक्ताओं की दरों में 35 से 40 फीसदी वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसी तरह अन्य श्रेणी में भी बिजली दरों में वृद्धि की प्रस्ताव दिया गया है। पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने स्वीकार किया तो उपभोक्ताओं की जेब कटनी तय है।

पावर कारपोरेशन ने नए उपभोक्ताओं की कनेक्शन की दरों के लिए कॉस्ट डाटा बुक को भी नियामक आयोग में दाखिल किया है। ऐसे में नया कनेक्शन लेना भी महंगा हो गया है। नए कनेक्शन की दर में करीब 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसी तरह नए कनेक्शन लेने पर विभिन्न तरह की सामग्री पर भी अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है। अभी तक नया कनेक्शन लेने पर पोल से 40 मीटर के दायरे में औसतन 10 हजार रुपया तक खर्च होता है। पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में गुप्त-चुप तरीके से निजीकरण के मसौदे पर सलाह लेने संबंधी प्रस्ताव भी पांच कॉपी में दाखिल कर दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रह क्षमता का आंकड़ा देते हुए घाटा करीब 19644 करोड़ दिखाया है।

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कारपोरेशन वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)

दाखिल कर चुका है। इसके सभी आंकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गए हैं। उपभोक्ताओं से आपत्तियां भी मांग ली गई है। सात जुलाई से बिजली दर की सुनवाई शुरू हो रही है। इस बीच अचानक श्रेणीवार बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकार करना असंवैधानिक है। नियामक आयोग द्वारा बिजली दर की सुनवाई शुरू करने के बीच कोई भी नया प्रस्ताव नहीं दाखिल किया जा सकता है। नियामक आयोग को यह प्रस्ताव खारिज करना चाहिए। क्योंकि करीब पांच साल पहले भी इस तरह का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे विद्युत उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद विद्युत नियामक अयोग ने खारिज कर दिया था।

प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर करीब 33122 करोड़ रुपया (सरप्लस) निकलने का मामला लगातार उठाया जा रहा है। इसे लेकर नियामक आयोग में याचिका भी लगाई गई है। विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांग है कि नोएडा पावर कंपनी की तरह ही उपभोक्ताओं के बकाया को बिजली दर में कमी करके लौटाया जा सकता है।

इस बीच पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल करके बिजली दरें बढ़ाने की मांग कर ली है।

## गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा का होगा मुकम्मल इंतजाम

20 जून को मुख्यमंत्री योगी करेंगे लोकार्पण

गोरखपुर, 17 जून (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रमुखता से शुभारंभ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए। इसका उद्देश्य प्रदेश के दक्षिणांचल को विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। धुरियापार की पहचान अति पिछड़े क्षेत्र के रूप

20 जून को मुख्यमंत्री सुरक्षा फ्लीट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जबकि आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा के लिए यहां लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर एटीएमएस (एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) भी लागू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा बनवाए गए गोरखपुर दक्षिणांचल के लिए गेम चेंजर साबित होगी। धुरियापार की पहचान अति पिछड़े क्षेत्र के रूप



कॉरेगे उसमें 5 इनोवा, 5 कैम्पर, 4 एम्बुलेंस, 2 क्रेन और 1 हाइड्रा वाहन शामिल हैं। यूपीडा के नोडल सिक्वोरिटी ऑफिसर राजेश पांडेय बताते हैं कि यूपीडा के इनोवा वाहन की पैट्रोलिंग 8-8 घंटे के शिफ्ट में लगातार होती रहेगी। हर वाहन में चार सेवानिवृत्त सैनिकों की ड्यूटी रहेगी। कैम्पर वाहन पीछे से खुले रहते हैं और इसमें ट्रैफिक कोन, रस्सी, रेडियम स्ट्रिप आदि की उपलब्धता रहती है। किसी स्थान पर किसी वाहन के खराब होने पर

या दुर्घटना होने पर ये वाहन तुरंत जाकर ट्रैफिक कोन, रस्सी और रेडियम स्ट्रिप से कवर कर देंगे ताकि अन्य वाहनों को कोई दिक्कत न हो।

इसके अलावा 91 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे पर हर 45 किमी पर मार्ग के दोनों तरफ एक-एक एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी ताकि आकस्मिक चिकित्सकीय जरूरत यात्रियों को तत्परता से अस्पताल भेजा जा सके। किसी वाहन में अचानक खराबी आने पर उसे सड़क से हटाने के लिए हर 45

किमी पर क्रेन और पूरे एक्सप्रेस-वे के लिए 1 हाइड्रा वाहन को तैनात किया जाएगा। यात्री और मध्यम मालवाहक वाहनों को क्रेन से ओर बड़े मालवाहक वाहनों को सड़क के नजदीक के चैनजे से उतार दिया जाएगा क्योंकि नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के दिशानिर्देश के मुताबिक एक्सप्रेस-वे पर खराब वाहनों को खड़ा नहीं किया जा सकता।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर आने वाले समय में एटीएमएस भी लागू करने की तैयारी है। इस

सिस्टम के तहत एक्सप्रेस-वे पर हर पांच किमी पर सीसी कैमरे लगाए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाती है। इसके अलावा एटीएमएस में रफ्तार सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नजर रखने के स्पीड कैमरे और एनपीआर (नम्बर प्लेट रीडर) की व्यवस्था भी होती है। एक्सप्रेस-वे पर रफ्तार सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तत्काल जांचकाी संबंधित जिले के एआरटीओ के पास चली जाती है।





के पासे सफेद रंग का कुर्ता व जंगिया होता था। पुष्प पाजामा तो किसी विशेष अवसर पर ही पहनते थे। सिर पर टोपी नसकती होती थी। युवक भी नोनो सिर नहीं रहते। वरुण के घर सूती पट्टाकी भी जरूर होता था। बुतुंगी पुरुष घर का हल्का-फुलका काम करते थे तथा 'बाण' बाटते थे। बाण, बिहुला पेड़ व शन पौधों के रेशे का बनता था। लंबे मोटे रस्से, पशुओं को बांधने वाले रस्से के अलावा चर्रापों के बुनने वाली पट्टाकी रिससयां सब हाथ से बाटी जाती थी। किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए आरा परिवार एकमत होत था। मुखिया की बात कोई नहीं एकलता था। प्रतिदिन सवेरे चार-पांच बजे से ही पहल जनों को दिनचर्या शुरू हो जाती थी। ज्यादा आयु-वर्ग की महिलाएँ रसोई में चौका देकर चूल्हे में आग जलाती तथा दही बिलोरेने के काम में लग जाती। जबकि दूसरी महिला दाल-सब्जी बनाने में व्यस्त हो जाती थी।



ने अपना चेहरा ढकते हुए उनकी बात सुनी और इसके बाद उन्होंने आंखें घुमाईं, जिससे उनकी नाराजगी साफ दिखी।  
यह स्पष्ट नहीं है कि मैक्रों ने उनसे क्या कहा था और दोनों नेताओं ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन यह लम्हा कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, कि 7 सम्मेलन की शानदार शुरुआत, मेलोनी कमाल की है, वो वैश्विक नेताओं के लिए अपनी नाराजगी नहीं छिपा नहीं रही हैं।

## न्यूज ब्रीफ



वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सीधीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को झटका दिया है। जज ने फैसले में कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) का अनुदान रद्द करने वाला ट्रम्प का निर्देश अमान्य और अंधेरा है। रद्द किए गए कुछ अनुदानों में एनजीबीटीवीयू आदि के कुछ अनुदान भी शामिल थे। एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, वह फैसला मेसासुसेट्स के सीधीय जज विलियम यंग ने सोमावार को सुनाया। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज यंग ने कहा कि यह सीधीय कानून का उल्लंघन है। ऐसा निर्देश प्रत्येकी भेदभावा है। अनुदान रद्द करने के बाद एक अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ और 16 राज्यों के समूह ने मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे कहा गया था कि अनुसंधान निधि में 1.8 बिलियन डालर तक की कटौती की गई है। जज ने फैसले में अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के संचार निदेशक एंड्रयू निक्सन ने फैसले पर कहा कि एजेंसी शोध के लिए वित्त पोषण समाप्त करने के अपने निर्णय पर कायम है। निक्सन ने कहा कि वह अभी दायर करने और आदेश पर रोक लगाने के लिए अपील करने सहित सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वादीगणों में हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ब्रिन्नी चॉल्टन भी शामिल हैं। चॉल्टन ने एक बयान में अदालत के फैसले पर खुशी जताई। अदालत ने सरकार के कार्यों की निंदा की और अनुदानों को बहाल करने का आदेश दिया।

ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकयन बोले - युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन हमले का जवाब देंगे



तेहरान/अंकारा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेइकयन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनका देश इजराइल के साथ युद्ध को और व्यापक नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो उसका उचित और अनुपातिक जवाब दिया जाएगा। यह बयान उन्होंने तुर्किए के राष्ट्रपति रेचप तैय्यप एर्दोगन के साथ जोन पर बातचीत के दौरान दिया, जिसकी जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आर्डाआरएण्ण और तुर्की की अनादोलु एजेंसी ने भी। पेजेइकयन ने कहा, ईरान ने यह युद्ध शुरू नहीं किया। इजराइली आक्रमण में हमारे वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और आम नागरिकों की जान गई है। लेकिन हमले के स्तर के मुताबिक हम जरूर जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में ईरान की भागीदारी पूरी तरह से खत्म बात पर निश्चय है कि जापान-रूस शासन (इजराइल) अपने क्षेत्रीय हमलों को रोकता है या नहीं। इस बीच, तुर्किए के राष्ट्रपति रेचप तैय्यप एर्दोगन ने कहा कि उनका देश संघर्ष को कम करने में सुविधाजनक भूमिका निभाने को तैयार है, और ईरान-अमेरिका परमाणु वार्ता की वापसी का समर्थन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि परिष्कृत एशिया में स्थिरता तुर्किए के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

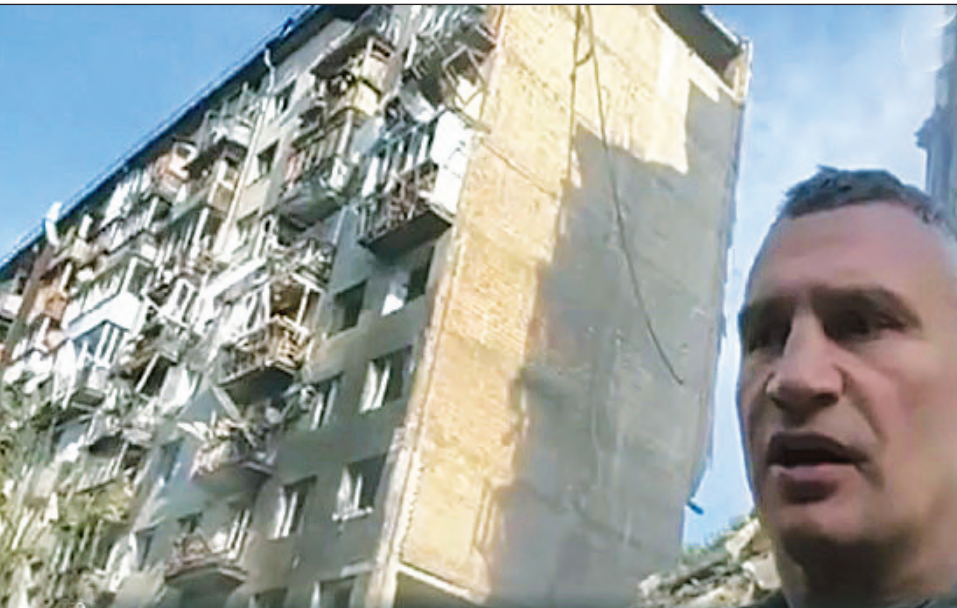
चीन को हो रही क्रॉस-बॉर्डर मैरिज से भारी परेशानी, जारी कर चुका है एडवाइजरी

ढाका। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश को क्रॉस बॉर्डर शादी करने से भी परेशानी हो सकती है, जी हां



क्रॉस-बॉर्डर मीजिंग की कोशिशों ने हालात बिगाड़े हैं। इसके चलते बांग्लादेश में काम करने वाले चीनी नागरिकों ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि शॉर्ट वीडियो देखकर बहकना नहीं, विदेशी शायदी के लालच में कानून मत तोड़ो। कुछ चीनी नागरिक बांग्लादेश से दुर्घटना खरीदने या अवैध शायदियों के लिए दलालों का सहारा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में मौजूद चीनी दूतावास ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी करके दुर्घटना खरीदने वाली चीनी नागरिकों को 'विदेशी दुर्घटना खरीदने' से दूर रहने और बांग्लादेश में शायदी करने से पहले गंभीरता से विचार करने की सलाह दी है। दूतावास का कहना था, चीनी कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या संस्था को विदेशी विवाह के लिए दलाली या बिचौली की भूमिका निभाने की इजाजत नहीं दी गई है।

# यूक्रेन की राजधानी पर पुतिन का भयंकर हमला, डोन और मिसाइलों से दहला कीव



**कीव, 17 जून (एजेंसियां) ।** कीव इन्फिडेंट के अनुसार, यह हमला लगभग नौ घंटे तक चला और इसमें ड्रोन और मिसाइलिक मिस्टाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की स्टाइ इम्पेरीज़ी सर्विस (उखड्ड) ने कहा कि कई आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में आग लग गई। कीव के मेयर विटाली क्लिचूको ने कहा कि हमले में कम से कम 114 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 68 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रूस ने यूक्रेन पर रात को उस समय मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, जिससे कम से कम 15 लोगों की मौत हो गयी और 116 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, 17

जून की रात को कीब में हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। कीब इंटीग्रेटेड के अनुसार, यह हमला लगभग नौ घंटे तक चला और इसमें ड्रोन् और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस (उख्रड) ने कहा कि कई आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में आग लग गई है। कीब के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि हमले में कम से कम 114 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 68 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

व्यापक रूप से प्रसारित इस फुटेज में एक ड्रोन को डारिन्त्स्की जिले में एक आवासीय इमारत में उड़ते हुए दिखाया गया है। एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, इमारत को 11वीं

से 18वीं मंजिल तक नुकसान पहुंचा है और कम से कम एक निवासी घायल हो गया है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की के भी इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। गृह मंत्री हहोर क्लिमेंको ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि हमले में छत्र लगने से घायल हुए एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गयी है। मंगलवार को रातभर विस्फोट की आवाजें सुनी गयीं। क्लिमेंको ने बताया कि हमले में एक रिहायशी इमारत में बने 30 अपार्टमेंट नष्ट हो गए। शहर के स्वियातोशिन्स्की और सोलोमिंस्की प्रांत में भी लोग घायल हुए हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि यूक्रेनी हवाई रक्षा प्रणाली के ध्वस्त हो जाने से गिरे मलबे के कारण शहर के दो अन्य प्रांतों में आग लग गयी है। जी-7 के मेजबान देश कनाडा ने जेलेन्स्की को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है जहां उनके विश्व नेताओं के साथ अलग-अलग मुलाकात करने की संभावना है। जेलेन्स्की को मंगलवार को कनाडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करनी थी लेकिन व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि ट्रंप पश्चिम एशिया में तनाव के कारण मंगलवार रात के बजाय सोमवार रात को वाशिंगटन लौट रहे हैं। रूस ने हाल के सप्ताहों में रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन और मिसाइल छोड़ी हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एजेंसी द्वारा रूसी क्षेत्र में हवाई अड्डों पर युद्धक विमानों को निशाना बनाने का अभियान शुरू किए जाने के बाद माँस्को ने हमले तेज कर दिए हैं।

## गाजा में पानी की भारी कमी



गाजा में पानी की भारी कमी के बीच ही एक अस्थाई शिविर के पास पानी के लिए मशक्कत करते हुए लोग

इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी आईआरआईबी के मुख्यालय पर लाइव प्रसारण के दौरान बमबारी की

तेहरान, 17 जून (एजेंसियां) ।

इजराइल ने कल ईरान के सरकारी टेलीविजन इस्लामि रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (आईआरआइबी) के मुख्यालय को निशाना बनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लाइव प्रसारण के दौरान बमबारी की। इस घटना की वीडियो विलफ भी सामने आई है। इसे बीबीसी ने अपने समाचार के साथ साझा किया है।



**بیانیہ دپیرخانہ شورای عالی امنیت ملی**

है, कांच के टूटने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अल जजीरा चैनल ने अपनी खबर में इस एंकर का नाम सहर इमामी बताया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने सेंट्रल ईरान में भी कई जगहों पर बमबारी की है। इस हमले में कुछ पत्रकारों के मारे जाने की सूचना है। मगर इसकी पुष्टि न तो

ईरान ने की है और न ही इजराइल ने। इजराइल ने कुदस फोर्स के कमांड सेंटर पर भी हमला किया है। यह ईरानी सेना की कुलीन और गुप्त शाखा है। यह मुख्य रूप से ईरान के विदेशी अभियानों देखती है। इसमें हिजबुल्लाह जैसे छद्म समूहों को आतंकी प्रशिक्षण और हथियार देना शामिल है।

## ईरान में मची भगदड़ से परेशान पाकिस्तान ने कहा- हम अपने यहां किसी को नहीं आने देंगे

इस्लामाबाद, 17 जून (एजेंसियां) ।

इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हैं। तहरान में भगदड़ मची है लोग इधर से उधर हो रहे हैं। सभी को अपनी अपनी जान बचाने की पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं सील का इस भी को आने से रोक दिया है।

सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच 909 किलोमीटर लंबे बाँड पर किसी भी शब्द के आने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त लगातार इजरायल की तरफ से हो रहे अटैक के बाद ईरान की राजधानी तेहरान सहित देश के अन्य शहरों में भगदड़ जैसी स्थिति है। लोग हमलों से बचने के लिए यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं।

ईरान-इजरायल जंग के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायल की आलोचना करते हुए मुस्लिम एकता की बात कही, लेकिन परमाणु हमले की धमकी की खबरों को खारिज



किया। इससे पहले ईरान के जनरल मोहसिन रजाई ने दावा किया था कि इजरायल अगर ईरान पर परमाणु हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाबी परमाणु हमला करेगा। पाकिस्तान ने इसका खंडन किया। कहा गया कि पाकिस्तान की रणनीति क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक हितों पर केंद्रित है, न कि परमाणु युद्ध पर।

इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर जबर्दस्त बमबारी की है। जवाब में

ईरान ने मिसाइल हमलों के साथ पलटवार किया। इस संघर्ष ने क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है।

ऐसे में पाकिस्तान का सीमा बंद करना उसके तनाव से पाकिस्तान होने का संकेत है। पाकिस्तान पहले भी बलुच विद्रोहियों और सीमा पर आतंकवाद के मुद्दों पर ईरान से तनाव का सामना कर चुका है। हाल की घटना से संकेत मिलता है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय युद्ध के संभावित प्रभावों, जैसे शरणार्थी मूवमेंट, तस्करी या आतंकी विद्रोहियों से बचने के लिए सतर्क हो रहा है।

हवाबा शरीफ सरकार का यह कदम उसकी एटिलड शरीफ राजनीतिक स्थिति को भी उजागर करता है। एक ओर पाकिस्तान ने इजरायल के मल्ला को निंदा करते हुए ईरान के प्रति एकजुटता दिखाई है। दूसरी ओर वह अफिरका और सऊदी अरब जैसे सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, जो ईरान के प्रति भी हैं।

## इजराइल-ईरान संघर्ष के बीच प्योंगयांग पहुंचे क्रेमलिन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी

योग्याग। इन्जइल-ईरान संघर्ष के बीच रूस और उत्तर कोरिया के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रैमलिन के पूर्वी सुरक्षा अधिकारी ए. बार् फ़िर ध्वजोंगान घुँघुँ है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जिसके पश्चिम एशिया में हालात विस्फोटक हैं और वैश्विक शक्तियाँ अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने में लगी हैं। रू उत्तर कोरिया घुरी वया दे रहे संकेत हालांकि यात्रा का कोई औपचारिक एजेंडा सार्वजनिक न मानना है। का कइ कम इन्जइल-ईरान संघर्ष हुए उठया गया है। सूत्रों की मानें तो यह मुलाकात की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह संभावना है के आदान-प्रदान और रणनीतिक साझेदारी प. अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी जहां ई कोरिया जैसे देशों के साथ तजोड़ कर वैश्व में अपना सकता है।



या है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का भावित भूराजनीतिक असंतुलन को देखते उत्तर कोरिया संबंधों को और गहरा करने ही है कि दोनों देश रक्षा सहयोग, हथियारों खर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अतृप्त करने में लगे हैं, वहीं रूस उत्तर पश्चिमी दबाव का जवाब देने की रणनीति











उपाय : आज गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।  
और 108 बार ऊं गं गणपतये नमः मंत्र का  
जप करें। इससे भगवान गणेश आपसे  
प्रसन्न होंगे।

जगन्नाथ जी की भक्ति करते रहे और हर रोज उनके दर्शन करते। दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों बाद प्रकृति चक्र घूमा और माधवदास युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधवदास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ ने दिन-रात उनकी सेवा की। बीमारी से कमजोर हो चुके माधवदास ने एक दिन भगवान जगन्नाथ से कहा- 'प्रभु! आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा- 'सिन्धु माधवदास! मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 दिन बचे हैं। प्रभु जगन्नाथ की बात सुनकर माधवदास ने कारावले हुए कहा-प्रभु! लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधवदास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधवदास ठीक हो गए लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधवदास जी को मोक्ष मिला और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं।











# सीएम नीतीश के तीन मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

## विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं

**पटना (एजेंसियां)।** मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता-नेत्री और बिहार सरकार के तीन मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। तीनों से नीतीश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथी ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, जमा खान और लेसी सिंह ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारों की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए वह लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहा है।

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। यह हमारे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है कि बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है,



जिन्होंने इस राष्ट्रीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शी नीतियों के चलते गरीबों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। बिहार के विकास की चर्चा आज देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी हो रही है, लेकिन विपक्ष को यह प्रगति दिखाई नहीं देती। यह उनकी संकीर्ण सोच का परिचायक है। राजद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजद परिवारवाद

जैसे विषयों पर बात करता है, तो इससे अधिक हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है।

मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह अनर्गल आरोपों का सहारा ले रहा है। लेकिन बिहार की जागरूक जनता उसकी हर चाल को नाकाम करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ पुनः सरकार

बनाएगी, समाज के सभी वर्गों का भरोसा नीतीश कुमार पर अटूट है।

मंत्री जनाब जमा खां ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के कल्याण और उत्थान के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों का सकारात्मक असर आज धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वहीं, विपक्ष की भूमिका अब केवल झूठ और भ्रम फैलाने तक सीमित रह गई है, जिसे जनता भली-भांति समझ

चुकी है। उन्होंने कहा कि शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए की स्थिति लगातार मजबूत हुई है और आगामी चुनाव में हम निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे।

दरअसल, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनाब जमा खां ने विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम में विधान परिषद में सतारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी एवं जद (यू0) अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रशेखरी एवं जनाब मेजर हैदर इकबाल एवं जनाब इरशाद अली आजाद भी उपस्थित थे।

## रंगदारी और हत्या के खिलाफ एकजुट हुए व्यापारी, उठाई पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग



### सीवान (एजेंसियां)।

बिहार में रंगदारी और हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम लोग और व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना जिले के नौबतपुर बाजार में व्यापारियों ने रंगदारी और अपराधियों की धमकियों के खिलाफ बाजार और दुकानों को पूरी तरह बंद रखा।

व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्थानीय प्रशासन से मुख्य बाजार में पुलिस चौकी की स्थापना और गश्ती बढ़ाने की

मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो वे अन्य राज्यों में पलायन को मजबूर होंगे।

गौरतलब है कि 11 फरवरी 2024 को नौबतपुर बाजार के व्यवसायी डॉ. ब्रजभानु प्रसाद की अपराधियों ने रंगदारी को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन अब वही अपराधी जेल से मृतक के बेटों पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं।

मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में व्यवसायी और मृतक के बेटे भवेश कुमार ने बताया कि 'अपराधी खुलेआम हथियार लेकर बाजार में घूमते हैं, जिससे डर का माहौल है।

अगर यही हाल रहा, तो हम व्यवसाय बंद कर यहां से पलायन कर जाएंगे।

व्यापारियों ने सवाल उठाया कि नौबतपुर थाना बाजार से महज 500 मीटर की दूरी पर है, इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं।

## मुख्तियाओं को मिलेगी 10 लाख तक की योजना स्वीकृति की शक्ति

### राज्य सरकार ने दी कई सौगातें

**सीतामढ़ी (एजेंसियां)।** बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। अब मुख्तिया समेत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को न केवल हथियार रखने का लाइसेंस मिलेगा, बल्कि उन्हें मिलने वाला मानदेय भी पहले से डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। साथ ही, पंचायत सरकार भवन के निर्माण से लेकर योजनाओं की स्वीकृति सीमा में भी वृद्धि की गई है।

यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित 'संवाद' भवन में पंचायत प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ हुई विशेष बैठक के बाद की गई। इसकी जानकारी सीतामढ़ी दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने दी।

पंचायती राज मंत्री ने बताया कि अब तक मनरेगा योजना के तहत मुख्तिया को 5 लाख रुपये तक की योजनाओं की स्वीकृति करने

का अधिकार था। अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार और दायरा दोनों बढ़ेंगे। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले इन सभी योजनाओं को धरातल पर उतार दिया जाए।

सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति (आर्मस लाइसेंस) के लिए आवेदन करने की सुविधा दी है।

जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करें। साथ ही, प्रतिनिधियों को पहले से डेढ़ गुना अधिक मासिक मानदेय मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।

राज्य के 1069 नए पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति दी गई है। जहां मुख्यालय वाले गांव में भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पास के गांव में भूमि लेकर भवन का निर्माण कराया जाएगा। पहले आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि अब

सामान्य मृत्यु पर भी प्रदान की जाएगी। साथ ही, बीमार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज की सुविधा दी जाएगी।

सरकार ने निर्णय लिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से अब 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की राशि से 15 लाख रुपये तक की योजनाएं विभागीय स्तर पर स्वीकृत की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 से पंचायत और 2007 से नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे आज बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

इन तमाम घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को सशक्त, प्रभावी और सम्मानजनक बनाने की दिशा में गंभीर है। इन फैसलों से न केवल प्रतिनिधियों के अधिकारों में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी पहले से अधिक मजबूत होगी।

## निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई

# आवास सहायक को रिश्तत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

### पटना (एजेंसियां)।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आवास सहायक को रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अरवल जिले में की गई है। इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जानकारी देते हुए कहा कि अरवल जिले के करपी प्रखंड अंतर्गत आवास सहायक सुनील कुमार सुमन को कार्यालय परिसर में दस हजार रुपये रिश्तत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

परिवादी रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के बालागढ़ गांव निवासी राम अवध सिंह के पुत्र भूषण कुमार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के



कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया थी कि आरोपी आवास सहायक सुनील कुमार सुमन प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त निकलवाने के एवज में रिश्तत की मांग कर रहा है। ब्यूरो द्वारा

परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्तत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम द्रष्ट्या आरोप सही पाये जाने के बाद निगरानी थाना में कांड सं0-

41/25 के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्राथमिकी दर्ज होते ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उप-अधीक्षक और अनुसंधानकर्ता शिव कुमार साह के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया। फिर टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त आवास सहायक सुनील कुमार सुमन को दस हजार रुपये रिश्तत लेते करपी प्रखंड के परिसर अरवल से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त से पूछताछ के बाद आरोपी नील कुमार सुमन को विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना में उपस्थापित किया जायेगा। फिलहाल अनुसंधान की आगे की कार्रवाई की जा रही है।

## छह एयरपोर्ट को लेकर नीतीश कुमार कैबिनेट में अहम फैसला बिहार में उड़ान योजना से होगा विकास



### पटना (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ने के दिये में एक और कदम बढ़ा दिया है। बिहार के छोटें हवाई अड्डों का फिर से विकास करने का उन्होंने फैसला लिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति भी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहस्रा स्थित हवाई अड्डों को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एमओयू को स्वीकृति प्रदान की गई है।

वरीय आईएसएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि हवाई अड्डों के विकास से छोटे शहरों और पिछड़े इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी।

इससे न केवल आम लोगों की यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार का यह कदम राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की नीति के अनुरूप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि विकास तभी सार्थक है, जब वह राज्य के हर कोने तक पहुंचे।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि

मधुबनी और वाल्मीकिनगर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। मुंगेर और मुजफ्फरपुर औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से अहम हैं। सहस्रा और वीरपुर को जोड़ने से कोसी और सीमांचल क्षेत्र को नई गति मिलेगी। इस फैसले को बिहार की आधारभूत संरचना और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने उड़ान योजना के बारे में भी जानकारी दी। कहा कि देश का आम नागरिक ('उड़ान') केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और मंझोले शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ती बनाना प्रमुख लक्ष्य है।

## बिहार पुलिस के जवान ने खुद के सिर में मारी गोली, मौत

### पटना (एजेंसियां)।

भभुआ पुलिस लाइन में पुलिस के एक जवान ने खुद को सिर में गोली मार ली। मृतक जवान की पहचान जमुई निवासी अमलेश कुमार (24) के रूप में हुई है। वह कैमूर में 2022 में योगदान किया था। वह भभुआ दंगा नियंत्रण पुलिस में था। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हरिमोहन शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।

घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि सोमवार की देर शाम भभुआ पुलिस लाइन में पुलिस के जवान अमलेश कुमार ने खुद के 147 गन से गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के जवान और पुलिसकर्मी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत आननफानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक उन्हें बनारस रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

घटना के संबंध में भभुआ पुलिस लाइन के डीएसपी



रामानंद मंडल ने बताया कि दंगा नियंत्रण में पदस्थापित पुलिस जवान ने अपने 147 गन से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर सभी पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और दरवाजा को तोड़ा तो उसमें जवान घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। लद्दलुहान स्थिति में देखकर वहां सभी के होश उड़ गए। तुरंत घटना की जानकारी कैमूर एसपी को दी गई और फिरघायल जवान को इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया, जहां बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

## चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना 20 लाख की संपत्ति ले उड़े



### सीवान (एजेंसियां)।

सीवान जिले के महादेवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आकोपुर गांव में एक बंद पड़े मकान से चोरों ने करीब 20 लाख रुपये की संपत्ति की चोरी कर ली। यह घटना तब घटी जब मकान मालिक छोटेलाल साह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए हुए थे। छोटेलाल साह ने बताया कि घर को ताला लगाकर सुरक्षित छोड़ा गया था, लेकिन चोरों ने ताला तोड़कर

नकदी, जेवरात और कीमती सामान चुरा लिया। स्थानीय ग्रामीणों को उस समय शक हुआ जब खेत में काम कर रहे लोगों ने मकान का ताला टूटा देखा, जिसके बाद उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। महादेवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रारंभिक

जांच में यह मामला पूरी तरह सुनियोजित चोरी का प्रतीत हो रहा है। छोटेलाल साह के अनुसार, इस वारदात से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और संपत्ति की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।